

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 13 अक्टूबर, 2022

अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दविस

वर्ष 2022 में आपदा न्यूनीकरण और इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दविस' का आयोजन किया जाता है। 'अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दविस' की स्थापना वर्ष 1989 में दुनिया भर में आपदा न्यूनीकरण के कार्य को बढ़ावा देने हेतु 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' (UNGA) के आह्वान पर की गई थी। वर्ष 2022 में इस दविस की थीम "2030 तक लोगों के लिये बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपदा जोखिम की जानकारी एवं आकलन की उपलब्धता तथा पहुँच में पर्याप्त वृद्धि" है, जो [सेंडाई फ्रेमवर्क](#) के लक्ष्य G पर केंद्रित है।

36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन

36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के सूरत में भव्य समारोह के साथ 12 अक्टूबर को सम्पन्न हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में खेलों के लिये सकारात्मक माहौल बनाया गया है। उपराष्ट्रपति ने खेल भावना विकसित करने पर जोर दिया। इसी के मद्देनजर भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के 37वें संस्करण की मेज़बानी के लिये गोवा में इसकी संभावनाओं की भी चर्चा की। खेल जगत के कई गणमान्य व्यक्तियों और लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बरिला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने इस समापन समारोह में हस्तिा ली। राष्ट्रीय खेलों के अंतिम दिन सर्वसिद्ध ने शानदार प्रदर्शन के साथ 61 स्वर्ण सहित कुल 128 पदक अपने नाम किये और शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने 39 स्वर्ण के साथ दूसरा तथा हरियाणा ने 38 स्वर्ण लेकर तीसरा स्थान हासिल किया।

'ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम'

केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री 14 अक्टूबर को रांची में 'ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम' (ग्राम अभ्यंता कार्यक्रम) के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस 165 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण पर आधारित है, इसका लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को विशिष्ट कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना है। संबंधित पायलट प्रोजेक्ट इस वर्ष मई में मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू किया गया था और इसके तहत पाँच राज्यों (मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र) को कवर किया गया था, पहले चरण के दौरान 152 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया, जिनमें से 132 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया और उन्हें प्रमाण पत्र दिये गए। इस दौरान प्रशिक्षण पाँच वर्षों यथा वदियुत एवं सौर ऊर्जा, कृषि यंत्रिकरण, ई-गवर्नेंस, नलसाज़ी (प्लंबिंग) व चर्नाई, दुपहिया वाहनों की मरम्मत और रखरखाव में प्रदान किया गया। इसका अगला चरण चार राज्यों यथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में आयोजित किया जाएगा, जिनमें कुल 165 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिये जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत करना और आजीविका के अवसरों के लिये प्रवास एवं साथ ही शहरों पर निर्भरता को सीमित करना है।